के भवन परिसरों के निर्माण को 1994-95 में मंजूरी दी गई है और 1995-96 के दौरान तवानगर जिला, होशंगाबाद में ऐसे ही एक विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के मेधावी बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों के निर्माणार्थ कल्याण मंत्रालय की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त अवसंरचनात्मक विकास, आवासीय विद्यालयों इत्यादि की स्थापना शामिल है।

विवरण

क्रम सं॰	विद्यालय का नाम और अवस्थिति	
1.	कन्या शिक्षा परिसर	चौकी, जिला राजनन्दगांव
2.	"	छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा
3.	"	जगदलपुर, जिला बस्तर
4.	"	अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
5.	"	पुष्पराजगढ़, जिला साहडोल
6.	"	कुक्षी, जिला धार
7.	गुरुकुल विद्यालय,	पेन्डरा रोड, जिला बिलासपुर
8.	आदर्श हायर सेकण्डरी स्कूल	डोंडी, जिला बिलासपुर
9.	"	चुरहट, जिला सीधी
10.	"	फरासगांव, जिला बस्तर
11.	"	जसपुरनगर, जिला रायगढ़
12.	"	सिझोरा, जिला मण्डला
13.	"	बड्वानी, जिला खरगांव
14.	"	सैलाना, जिला रतलाम
15.	"	तवानगर, जिला होशंगाबाद

Allotment of land under 'Bhoomi Putra Yojana'

7558. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will be Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the nunmber of landless families among Pahari Korva and Birhora tribes of Madhya Pradesh, who are on the verge of extinction as per the position available till July, 1994;

(b) what is the number of such families amongst them that have since been provided with agricultural land under "Bhoomi Putra Yojana" alongwith the number of families who are likely to be provided with such land during the year 1994-95 and 1995-96;

(c) what is the total area of land belonging to the family of Chief of Pahari Korva tribe late Uchit Narayan Singh, which has been grabbed fraudulently by some persons together with the action being taken by Government for getting the said land restored to that family;

(d) what is the total area of the forest land taken possession of by Pahari Korva and Birhora families pending settlement/regularisation; and

(e) what are the details of the agricultural land given on leese to certain families of these tribes under the earlier settlement/regularisation of forest land?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (e) The information is being collected from the State Government of Madhya Pradesh and the same, of its receipt, will be laid on the Table of the House.

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दिया जाना

7559. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से गत तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार तथा चालू

वर्ष के दौरान अब तक जिला-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन जिला-वार स्वीकृत किये गये और कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) इस सहायता की स्वीकृति देते समय किन मानदंडों/तथ्यों पर विचार किया गया;

(घ) स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) एक विवरण नीचे दिया गया है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान निर्मुक्त करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं:—

(1) संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत न्यास अथवा कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्थान होना चाहिए।

(2) संगठन को कम से कम 2 वर्षों से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।

(3) संगठन को वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए तथा योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल हुए कुल व्यय का कम से कम 10% वहन करने की स्थिति में होना चाहिए।

(4) संगठन का आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

(घ) 42 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(ङ) पात्र लम्बित आवेदन पत्रों पर, जहां कहीं आवश्यक हो, संगठन तथा राज्य सरकार से आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चालू अथवा अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा।

विवरण

मध्य प्रदेश में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त हुए वर्षवार और जिलावार आवेदन पत्र दर्शाने वाला विवरण

1	2	3	4	5
क्रम सं॰	जिला	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	मंजूर की गई राशि
1	जबलपुर	3	2	4.10
2.	गुना	1	1	1.77
3.	बैस्ट नीमद	1	1	4.00
4.	बस्तर	1	1	3.88
5.	कापडला	1	—	—
6.	भोपाल	5	4	4.89
7.	रायपुर	1	1	0.60
8.	इन्दौर	8	5	11.20
9.	जसहुआ	1	—	—
				1993-94
1.	जबलपुर	6	8	11.03
2.	गुना	1	1	4.82
3	मुरैना	2	1	0.75
4.	दुर्ग	2	1	1.29
5	बस्तर	3	1	11.89
6	बेस्ट नीमद	1	1	3.00
7	चित्रकूट	1	—	—
8.	इन्दौर	13	7	11.45
9.	रायपुर	1	1	0.95
10.	भोपाल	3	—	—
11	सागर	1	1	1.35
12.	मन्दसौर	1	—	1.50
13.	बरवान	1	1	1.50
14	बेटेल			
15.	रायगढ़	2	1	2.16
16.	भिलाई	1	1	2.50
17.	जूनागढ़	1	—	—
				1994-95

1	2	3	4	5
क्रम सं॰	जिला	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	मंजूर की गई राशि
1.	जबलपुर	14	12	26.81
2.	गुना	2	1	3.50
3.	मुरैना	2	2	2.48
4.	दुर्ग	--	1 (लम्बित आवेदन	1 177
5.	बस्तर	1	1	3.19
6.	भोपाल	12	8	15.07
7.	रायपुर	1	1	1.76
8.	इन्दौर	16	11	26.54
9.	सतना	1	1	0.53
10.	खरगोन	1	1	0.71
11.	मंदसौर	1	1	0.14
12.	धार	1	--	--
13.	नीमच	1	1	1.44
14.	बरवानी	1	1	0.50
15.	भिलाई	2	2	2.42
16.	शहडोल	1	--	--
17.	विदिशा	1	--	--
18.	सरगुजा	1	--	--
				1995-96
1.	दुर्ग	1	1	1.68
2.	इन्दौर	1	--	--
3.	जबलपुर	1	--	--

Unemployment among Rural and Tribal Youths in Gujarat

7560. SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of unemployed rural and tribal youths in Gujarat provided employment so far under various programmes during each of the last three years, year-wise and district-wise;

(b) the extent of increase registered in the number of unemployed rural and tribal youths in the state between March 1993 to March 1994;

(c) the target fixed and the achievement made for the rural and tribal employment during the last three years; and

(d) the details of special measures taken to provide more employment to the unemployed rural and tribal youths?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Statement is given. (*See* Below)

(b) As on March, 1993, the number of unemployed rural and tribal youths was 93,850; and on March, 1994, the number was 90,275. There was no increase between March, 1993 to March, 1994.

(c) No targets are fixed.

(d) The special measures taken by the State Government to provide more employment to the unemployed rural and tribal youth are as under:—

1. Industrial 'Bharati Melas' (Recruitment Fairs) are being organised in industrial areas.

2. Minimum unemployment programme is launched in 34 talukas of 17 Districts, to provide employment training, and self-employment.

3. Seven (7) Youth Employment Exchanges are working in the State for Rural and Tribal Youths.

4. Prime Minister's new Scheme of Self-Employment is receiving top priority in motivational camps of unemployed youths.

5. Pre-examination training centres are started to impart training to the ST candidates appearing in the competative examinations conducted by Banking Service Recruitment Board, Rly., Rectt. Board, LIC and other Insurance Corporations, Public Service Commissions and other Govt./Semi-Govt. Organisations.

6 In tribal area, Vocational Training Centres have been started to give training in various vocational courses to ST youth. Loan/Subsidy upto Rs. 10,000/- for self-employment is also provided after completion of training.